

सं. ग्रो. पि./रोहतक/7-85/7552.—पूर्वि हरियाणा के राज्यपाल द्वीरु राय है कि मैं शोहर स्वीकृति मिल, रोहतक, ते धर्मिक श्री राज कुमार तथा उसके प्रदन्धकों के मध्य इसमें इसके दाद सिद्धित पामसे में कोई धौखोणि पिंडाद है;

प्रो धंकि दूरियाना के राज्यपाल विदाय को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना कांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, ग्रौजोपिक दिवाद अधिनियम, 1947, की शारा 10 की उपधारा (1) के अन्दर (ग) द्वारा प्रदान की गई शास्त्रियों का प्रयोग उत्तरो हुए हृरियाणा के राज्यपाल इसने द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई) -अम/70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की शारा 7 के प्रधीन गठित अम न्यायालय, रोहतक, की विदादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीये किंवा भामला न्यायनीय हो लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रदर्शनी तथा अभिक के दोष पा को विदादप्रस्त मामला है या उक्त दिवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

यथा श्री राज कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोपचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का दृष्टान्त है?

दिनांक 12 मार्च, 1985

सं. घो. वि./एफ. डो./९-८५/९४२३.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है की मैं गशोका आईस एफ. जनरल मित, रिवाड़ी रोड, नारनोल के अधिक श्री गुरदियाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित भाषण में कोई ग्रीष्मेगिक विदाह है ;

ग्रीष्म और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विदाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना गांधीनीय समझते हैं ;

इसलिये, प्रब, मौजूदगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपचारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई अधिकारियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम द्वी धारा 7 के प्रबोन्न गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायिकाद्य के द्वारा निर्दिष्ट करते हुए, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला।

क्या श्री गुरदियाल सिंह की सेवाओं का समापन व्योपेचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हुक्मदार है ?

सं० श्रो० विठ०/फरीदाबाद/२-८५/९४४६.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल फि राय है कि मै० आटो ग्लाइड प्रा० लि० प्लाट न० ६४, सैक्टर-६, फरीदा बाद, के श्रमिक श्री महादुर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिपित मामले में जोई श्रोद्योगिक विधाद है :

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की शारा 10 की उप शारा (1) के अंडे (ग) द्वारा प्रदान की गई अप्रियतयों ना प्रयोग करते हुए हरियाला के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिपूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की शारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत मध्यवा सम्बन्धित मामला है :—

नया थी बहादुर सिंह की सेवाओं का समापन भ्यायोपित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का दृष्टिकोण है?

सं. शो.दि./फरीदाबाद/2-85/9453.—चूंजि द्विरियापा के राज्यपाल की राय है कि मैं आटो ग्लाइड प्रा. लि., प्लाट नं. 64, सैन्टर 6, फरीदाबाद के शमिल वी महेन्द्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद सिंहित सामग्री में जोई शैदीप्रतिक्रियादृष्टि :

શ્રોત એવિધિ કરિયાણ એ યાજ્ઞવોલ વિવાહ એ શાશ્વતમિર્યમ હેઠળ નિર્દિષ્ટ રૂરા બાંદ્ધનીય કુમણાંથે એ :

इसलिए, अब, श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम 88-श्रम/57/1-245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अधिकारी संबंधित मामला है :—

क्या श्री महेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. श्रो. वि./एक.डी./35-85/9460.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै. जी. जी. टैक्सटाइल 22-ए, इण्डस्ट्रीजल एरिया, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री विभिषण तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/1-245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अधिकारी संबंधित मामला है :—

क्या श्री विभिषण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 21 भार्च, 1985

सं. श्रो. वि./भिवा/गि/8-85/11541.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै. मोहन इलंकटो स्टील लि., अभानी, के श्रमिक श्री फतेह सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम 70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए-एस-प्रां. (ई)-श्रम/70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री फतेह सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है

सं. श्रो. वि./रोहतक/234-84/11548.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मोहन स्वीनिंग मिल, रोहतक, के श्रमिक श्री रोहतास तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए-एस-प्रां. (ई)-श्रम/70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा

उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादप्रस्त या उसमें सुनवाई नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय देते निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :—

क्या श्री रंगेन्द्र की सेवाओं का समापन न्योनित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस गहरत का हृदयर है ?

सं. ओ. वि./रोहतक/231-84/11555.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मैं रोहत क्षेत्र मिल, रोहतक, के श्रमिक श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद निवित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करता बांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9041—श्रम-70/325, दिनांक 1 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3861-ए-एस-ओ. (ई)-श्रम/70/1343, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादप्रस्त या उसके सुनवाई नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुनवाई न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राजेन्द्र प्रसाद की सेवाओं का समापन न्योनित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हृदयर है ?

सं. ओ. वि./रोहतक/233-84/11562.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं संलग्न स्पीनिंग मिल, रोहतक, के श्रमिक श्री रामराजी नाल तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद निवित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करता बांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641—श्रम/10/325/3, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित भरपूरी अधिसूचना सं. 3864-ए-एस-ओ. (ई)-श्रम/70/1348, दिनांक 8 नवम्बर, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादप्रस्त या उसके सुनवाई नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री रामराजी नाल की सेवाओं का समापन न्योनित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हृदयर है ?

दिनांक 4 मार्च, 1985

सं. ओ. वि./एफ.डी./8056.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं जीला इन्टर प्रासिज, प्लाट नं. 17, मार्किंट नं. 5, एन. आई.टी. फरीदाबाद के श्रमिक श्री पुनी तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद निवित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करता बांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-ब्र. 63/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11215, दिनांक 7 करवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादप्रस्त या उसके सुनवाई नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री पुनी की सेवाओं का समापन न्योनित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हृदयर है ?

प. प्रो.वि.कर्णोनाम: 11/2, 4-84/30 विवाह के राज्यान को राय है कि मे. डावरी वॉलस्टील एण्ड इन्जिनियरिंग क. वि. नाटन. 136, सैक्स नं. 1 करीबाद के शिक्षित तथा नानक भन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद विविध मानसे में कोई शोश्यकिक विवाद है :

प्रौढ़ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विराज ने न्यायितार्ग। हेतु निर्दिष्ट करता वांछनीय समझते हैं।

इसीपरे, प्रब्र, श्रीदंगिल विवाद प्रांतिका 1947, को धारा 10 को उपाय (1) के बाद (ग) द्वारा प्रदान को गई अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसियां के राज्यान्तर इनके द्वारा सरकारी प्रविष्टियां सं. 5115-3-श्रम/68/15254, दिनांक 20 जन, 1958, के साथ पहले ही अधिसूचना सं. 11493-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिसूचनायम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, करातीवाद, को विवादप्रस्त या उससे मुंगेत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायिक रूपित विवादप्रस्त करते हैं जो कि उस प्रक्रिया तक प्रविष्टों के बोन या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से मुंगेत अवश्य संबंधित मामला है।—

क्या धूम निक चन्द की सेवाओं का समान व्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

म० श्रो. वि./रु. लो./34-85/8070.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि म० इण्डिया फोर्ज ए०ड ड्राम्यू स्ट्रेसिंग वि०, १०/३, मधुरा रोड, फरीदाबाद के अधिक श्री मुरेश जर्मी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई आव्योगिक विवाद है :

और वक्ति हुग्याण के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इमण्डि, अव, श्रीकृष्ण किंवद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने पर हस्तियाण के नायपाल उस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम/68/15254, दिनांक 20 जून, 1958, के साथ पड़ी हुई अधिकृत नं. 11493-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उस अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अमन्यान्य, करीदाराएँ, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे यम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय के लिए नियमित करते हैं जो यह उस प्रबन्धकों तथा अधिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है ।

क्या श्री मुरोश शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ. फि./एक. डा./103-84/8077.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० एन्सेन काटन मिल्ज, लिं०, मध्यराज्या रोड़ ब लवगढ़ के अधिक श्री मनी वन्सरी देवी तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई धीर्घांगिक विवाद है;

और वक्त हरियाणा के गज्यपाल निवास को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चांठनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विद्याव अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के बाबत (ग) द्वारा प्राप्त की गई जमियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के गजपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम/१८/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के माध्यम से पढ़कर हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1968, द्वारा उक्त अधिनियम को धारा 1 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, करादावाद, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय को लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा अमिक के बीच या नो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है।—

क्या श्री मरो कुमारी देवी की मेराश्रो का गमाणन व्यापाच्चि । तथा ठीक है? परि नहीं, तो वह किस राहत की हूकदार है?

म. श्रोति/हि १२/२९-४-४/८१०५.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल ने राय है कि मैं इसार्थ संस्कृत नोआपरेटिव वैधि विव. हि १२, के अधिक श्री ओम प्रभास तथा उसने प्रबन्धमानों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मीठेगिक विवाद है;

प्रौर चुकि हरियांग के राज्यपाल निदाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 ए-एस.ओ. (ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत प्रथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री ओम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ.वि./हिसार/76-84/8117.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं हरियाणा राज्य परिवहन, फिरसा, (2) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री राम प्रत-परिचालक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए-एस.ओ. (ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत प्रथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री राम प्रत-परिचालक की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ.वि./हिसार/144-84/8124.—इरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं दो बैंक स्टाफ भर्ती अबैन (एम०ई०) थिफ्ट एण्ड क्रेडिट समिति लि., हिसार, के श्रमिक श्री राजीव चड्डा तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए-एस.ओ. (ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री राजीव चड्डा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ.वि./एफ.डी./31-85/8137.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं कोहिनूर पैन्ट्स प्रा. लि., 14/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री लल वहादुर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत प्रथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री लल वहादुर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?